



अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय- 3, मार्बल आर्च, सेनापती बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016.
दूरभाष : (022) 24306321 / 24378866 फैक्स : 24313938 ई-मेल : abvpkendra@gmail.com

दिनांक: 14 फरवरी 2022

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

लावण्या को न्याय की माँग करती अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री को तमिलनाडु पुलिस ने किया गिरफ्तार

उच्चतम न्यायालय ने लावण्या आत्महत्या मामले में न्याय हेतु लड़ने वाले देश के युवाओं की सुनी है गुहार:

ABVP

तमिलनाडु के तंजावुर जिले के सेक्रेड हाई स्कूल में मतांतरण के दबाव के कारण आत्महत्या को मजबूर होने वाली छात्रा, लावण्या को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री स्टालिन के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभाविप के कार्यकर्ताओं से पुलिस ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हुए अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी, राष्ट्रीय मंत्री श्री मुथु रामलिंगम, दक्षिण तमिलनाडु प्रांत मंत्री सुशीला सहित कई अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है।

लावण्या आत्महत्या मामले में राज्य सरकार की असंवेदनशीलता इस बात से प्रदर्शित होती है कि सरकार मद्रास उच्च न्यायालय के सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी लगाने पहुँच गई थी। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए और उच्च न्यायालय के फैसले को मान्य रखते हुए, मामला सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। जिससे लावण्या को न्याय मिले यह माँग हेतु संघर्षरत युवाओं को अब न्याय की आस जगी है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री श्री गजेन्द्र तोमर ने कहा, "तमिलनाडु सरकार तथा प्रशासन, लावण्या की आत्महत्या के मामले को दबाने के लिए सारे संभव हथकंडे अपना रहे हैं परंतु अभाविप का प्रत्येक कार्यकर्ता लावण्या को न्याय मिलने तक संघर्षरत रहने के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी गलती और मिशनरियों के दुष्कर्म को छिपाने के लिए राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना करने से नहीं चूक रही है। हम लावण्या को न्याय मिलने तक लड़ते रहेंगे।"

कु. प्रेरणा पवार, अभाविप राष्ट्रीय मंत्री ने कहा, "तमिलनाडु सरकार ने बर्बरता की हदों को पार कर दिया है। सरकार लावण्या की आवाज़ को दबाने का हर सम्भव प्रयास कर रही है परंतु अभाविप लावण्या की लड़ाई को लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। हम मतांतरण को रोकने के लिए क़ानून बनाने के लिए भी सरकार से आग्रह करेंगे ताकि पुनः किसी भी विद्यार्थी को ऐसे वीभत्स और दुर्दांत कृत्य का सामना न करना पड़े।"

(यह प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रीय कार्यालय मंत्री सुमित पाण्डेय द्वारा जारी की गई है।)